जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 308 प्रभात हिण्डौन सिटी, गुरूवार 11 सितम्बर, 2025 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

सुप्रीम कोर्ट के मु. न्यायाधीश गवई ने चेताया राज्यपालों की भूमिका पर

मुख्य न्यायाधीश ने नेपाल का उदाहरण देकर कहा, अगर सरकार के दो स्तम्भों, विधायिका व प्रशासन में आपस में गतिरोध अनियंत्रित रहे तो उसका परिणाम अस्थिरता व अनिश्चितता होती है, जो पड़ोसी देश नेपाल में देखी जा रही है।

- जाल खंबात -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली 10 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक दुर्लभ और कड़ी टिप्पणी करते हुए केन्द्र सरकार को चेतावनी दी है कि राज्यपालों द्वारा राज्य विधेयकों को मंजूरी देने में हो रही देरी पर विचार करते समय उसे भारत के पड़ोस, विशेष कर नेपाल, में हो रही घटनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने राष्ट्रपति से जुड़े एक संदर्भ की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, जिसने राजनीतिक और क़ानूनी हलकों में हलचल मचा दी है। कहीं चिंता जताई जा रही है तो कहीं इसे सही ठहराया जा रहा है।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 12 अप्रैल के आदेश से जुड़ा है, जिसमें राज्यपालों और भारत के राष्ट्रपति के लिए राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों से निपटने की समय सीमा तय की गई थी। इस फ़ैसले का मक़सद था, ऐसे विधेयकों पर अनिश्चित काल तक कोई कार्रवाई नहीं होने की प्रवृत्ति को रोकना।

- जैसा कि, विदित ही है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह मामला प्रस्तुत है, कि क्या राज्यपाल असीमित समय तक उनके सम्मुख विधानसभा से पारित विधेयक को पेंडिंग रख सकते हैं।
- मुख्य न्यायाधीश की इस मामले में चेतावनी जैसी टिप्पणी से विपक्ष काफी प्रसन्न है, तथा यह महसूस कर रहा है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण में उनके पक्ष व तर्क का मूक समर्थन किया है।

केन्द्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्यपालों की विवेकाधिकार शक्तियों का ज़ोरदार बचाव किया। लेकिन मुख्य न्यायाधीश गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सवाल उठाया कि राज्यपाल महीनों तक विधेयकों को रोकर क्यों रखते हैं, कभी-कभी तो संविधान में तय एक महीने की सीमा से भी अधिक समय तक।

इसी संदर्भ में अदालत ने यह नसीहत दी, "हमें यह देखना होगा कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है"। क़ानून विशेषज्ञों ने इसे नेपाल की ओर इशारा माना, जहाँ कार्यपालिका और विधायिका के बीच बार-बार के टकराव ने राजनीतिक अस्थिरता पैदा की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेपाल का हवाला देना, याद दिलाने और चेतावनी, दोनों के तौर पर देखा जा रहा है, कि भारत सरकार को भी ऐसे संस्थागत टकराव से बचना होगा।

इस टिप्पणी ने तीव्र राजनीतिक प्रतिक्रिया को जन्म दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कोर्ट की बात का स्वागत करते हुए मोदी सरकार से अपील की कि संघीय ढाँचे को कमज़ोर करने के ख़तरे को गंभीरता से लें। उनका कहना था कि राज्यपालों को विपक्ष-शासित राज्यों में विधायी प्रक्रिया रोकने के लिए लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नेपाल में 15,000 कैदी जेल से फरार

काठमांडू, 10 सितंबर। नेपाल में बीते दो दिनों में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की उग्र लहर के चलते जेलों में बंद करीब 15 हज़ार से ज्यादा कैदी फरार हो चुके हैं।

इसे विश्व इतिहास में जेल तोड़कर भागने की सबसे बड़ी घटना माना जा रहा है। गिनीज़ वर्ल्ड रिकार्ड के अनुसार इससे पहले 1979 में ईरान में हुए तख्ता पलट में करीब 11 हज़ार कैदी भाग गए थे।

- हिंसक प्रदर्शनों के बीच आंदोलनकारियों ने जेलों पर धावा बोल दिया। इसमें 15,000 से ज्यादा कैदियों के भागने की खबर है। जेल से भागने की यह संभवतया इतिहास की सबसे बड़ी घटना है।

जेलें तोड़ने की शुरुआत तब हुई जब युवा प्रदर्शनकारियों ने कई जेलों में धावा बोल दिया और उनके प्रशासनिक भवनों में आग लगा दी। इन लोगों ने जेल के दरवाज़े जबरन खोल दिए। बुधवार शाम तक, प्रारंभिक रिपोर्टों ने पुष्टि की कि 25 से ज़्यादा जेलों से 15,000 से ज़्यादा कैदी भाग गए थे, जिनमें से केवल कुछ ही स्वेच्छा से लौटे या उन्हें फिर से गिरफ़्तार किया गया।

पोलैण्ड ने रुस के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया

रुस ने, जैसा कि विदित ही है, अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया यूक्रेन पर, ड्रोन व हवाईजहाजों की बमबारी से

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 सितंबर। हर गुज़रते दिन के साथ यूरोप में शांति कम होती जा रही है तथा एक गंभीर युद्ध छिड़ने की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। प्रथम विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश सचिव अर्ल ग्रे ने भविष्यवाणी करते हुए शोक व्यक्त किया था, कि "यूरोप भर में रोशनी बुझ रही है। हो सकता है कि हम इन्हें अपनी ज़िंदगी में दोबारा जलते हुए न देखें।"

पोलैंड ने बुधवार को घोषणा की कि उसने रविवार को अपने आसमान में रूसी ड्रोन मार गिराए, जब रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। शांति और समाधान की ओर कुछ छोटे कदम उठने के बजाय, हालात और अंधकारमय होते जा रहे हैं।

स्थिति और ख़तरनाक बनती जा रही है, क्योंकि एक पक्ष, पश्चिमी सहयोगी और अमेरिका, केवल रूस के खिलाफ कार्रवाई की धमकियाँ दे रहा है, वहीं दूसरी ओर रूस बिना किसी डर और रोक-टोक के अपनी स्थिति और सख़्त कर रहा है, मानो उसे पश्चिमी धमकियों की कोई परवाह ही नहीं।

सैन्य गतिविधियों में तेजी और व्यापक सक्रिय टकराव पूरे महाद्वीप में किसी बड़े संघर्ष की आशंका को और बढ़ा रहे हैं। रूस साफ़ तौर पर एक निर्णायक जीत दिखाने की बेचैनी में शत्रुता का स्तर बढ़ा रहा है और यूक्रेन को नुक़सान पहुँचा रहा है। अब पड़ोसी देशों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

- पोलैण्ड के हवाई क्षेत्र (एयर स्पेस) में जो ड्रोन पहुंचे, वो रुस के यूक्रेन पर किये गये भारी ड्रोन आक्रमण के, बिखरे हुए ड्रोन ही हैं।
- पोलैण्ड, नाटो देशों का आव्हान कर रहा है, कि वे अपने नाटो के सदस्य के रुप में किये वादे को पूर्ण करने की दृष्टि से अब रुस पर आक्रामक कार्यवाही करें।
- रुस इन वादों की पूर्ति तथा और आक्रामक होने की धमकी को कतई गंभीरता से नहीं ले रहा है।
- ये सब संकेत हैं, तृतीय विश्वयुद्ध की तारीख नज़दीक होने के।
- अमेरिका, यूरोपीय देशों को प्रोत्साहित कर रहा है, कि चीन व भारत पर दंडात्मक टैरिफ लगाये।
- हालात, सभी देशों को युद्ध की ओर घसीट रहे हैं।

पोलैंड अब शत्रुता के विस्तार में सबसे आगे खड़ा दिखाई दे रहा है, और पोलैण्ड के आसमान में अब तक हुई घुसपैठ, उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन 'नाटो' को, अपने सामूहिक रक्षा समझौते को लागू करने की चुनौती दे रही है। नाटो सदस्य देशों ने संगठन में शामिल होते समय शपथ ली थी कि किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा।

पुतिन यह संदेश दे रहे हैं कि वे किसी भी क़ीमत पर यूक्रेन में अपना लक्ष्य हासिल करने पर आमादा हैं। तीव्र होते संघर्ष से वे यह जताना चाहते हैं कि अगर यूरोपीय सहयोगी अपने सैनिक भेजते हैं या और सक्रिय हस्तक्षेप करते हैं, तो वे उनसे भी लड़ने को तैयार हैं।

पश्चिमी यूरोपीय देशों ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या नेपाल की पहली चीफ जस्टिस सुशीला कार्की अतंरिम सरकार की मुखिया होंगी?

जैनरेशन ज़ैड ने सुशीला कार्की का नाम प्रस्तावित किया है पर अभी चर्चा चल रही है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 सितंबर। सरकार और राजनीतिक दलों के नेताओं के कथित भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद, नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की अब अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में उभर रही हैं।

उनका नाम जेनरेशन ज़ैड द्वारा प्रस्तावित किया गया है और इस पर विचार-विमर्श अभी भी जारी है।

युवा पीढ़ी के हिंसक प्रदर्शनों ने नेपाल को अराजकता में डाल दिया, जिससे पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली को कल इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद नेपाली सेना ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप किया। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और

- प्रधानमंत्री ओली के भाग जाने के बाद यही चर्चा चल रही है कि अंतरिम सरकार का नेता कौन होगा। नेपाल के एक एनजीओ "हामी नेपाल" के सुदीप गुरूंग, जो कि जैनरेशन ज़ैड आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, ने कार्की के नाम का प्रस्ताव रखा।
- भ्रष्ट नेताओं पर सख्त कार्यवाही के कारण उन पर महाभियोग तक चलाने का प्रयास किया गया था।
- अतंरिम सरकार के नेतृत्व के लिए काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह, धरान के मेयर हरका सम्पर्ग, सागर धाकाल और राष्ट्र बिमोचन तिमलसेना का नाम भी चर्चा में है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विधायक ऋतु बनावत कैलाश यात्रा में फंसी

भरतपुर, 10 सितम्बर। विधायक ऋतु बनावत कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान चीन-नेपाल बॉर्डर के पुरांग क्षेत्र में फंस गई हैं।

3 से 11 सितंबर तक की इस यात्रा के अंतिम चरण में नेपाल में चल रहे विद्रोह और अस्थिर हालात के चलते, यात्रा दल को रोक दिया गया है। राहत की बात है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैंढ म ने तुरंत एक्शन लिया है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि घबराएं नहीं, हर यात्री को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। ऋतु बनावत भरतपुर जिले के बयाना रूपवास क्षेत्र से विधायक हैं।

- नेपाल के अस्थिर हालात के कारण यात्रा दल को चीन - नेपाल बॉर्डर पर पुरांग क्षेत्र में रोक दिया गया।

क्या मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना नीतीश का मास्टर स्ट्रोक साबित होगी?

महिला सशक्तिकरण की योजना का मूल संदेश है महिला वोट बैंक को साधना

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 10 सितम्बर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" को महिलाओं की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे छुपा बिहार चुनाव का संदेश भी साफ झलकता है।

यह वादा दिखने में भले ही सीधा-सादा लगे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा हो सकता है, आज 10,000 रुपये और भविष्य में 2 लाख रुपये तक की सहायता। हर बिहारी परिवार की एक महिला, यदि वह और उसका पति आयकर दाता नहीं हैं, को स्व-रोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभिक राशि (सीड मनी) दी जाएगी। छह महीने बाद, अगर व्यवसाय में संभावना दिखती है, तो सरकार 2 लाख रुपये की पूंजी निवेश सहायता देगी।

- सरकार में आने के बाद से नीतीश ने नशाबंदी लागू करना, पंचायत व शहरी निकाय में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देना, पुलिस व सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण देना तथा छात्राओं को साइकिल व स्कॉलरशिप देने जैसी योजनाएं लागू कर अपना मजबूत महिला वोट बैंक खड़ा किया है, जो जातिवादी राजनीति की काट भी साबित हुआ है।
- इस वोट बैंक का नीतीश को लाभ भी मिला है। हर बार चुनावों में पोलिंग बूथ पर महिलाओं की लम्बी कतारें इस बात का प्रमाण हैं। बिहार में महिलाएं नीतीश के लिए किंगमेकर की भूमिका में नज़र आ रही हैं।

7 सितंबर से शुरू हुई इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया खुली है। इसे एक ऐसा प्रयास बताया जा रहा है, जो महिलाओं को स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता और उद्यिमता की ओर बढ़ाएगा। लेकिन इसका राजनीतिक संदेश भी साफ है, उन विधानसभा क्षेत्रों की महिला मतदाताओं का सशक्तिकरण और समर्थन सुनिश्चित करना, जिन्होंने बीते दो दशकों से नीतीश कुमार का साथ दिया है।

नीतीश कुमार ने नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार महिलाओं को अपनी स्थायी राजनीतिक आधारशिला बनाने की दिशा में काम किया है। सामाजिक कल्याण से लेकर शिक्षा तक, शराबबंदी से लेकर शासन में आरक्षण तक, नीतीश की राजनीति ने महिलाओं को बिहार की राजनीतिक कहानी के केन्द्र में ला खड़ा किया है।

जहां लंबे समय से चुनावी गणित का आधार जाति रही है, वहीं नीतीश ने इसके जवाब में लिंग आधारित वोट बैंक तैयार किया, जो भारतीय राजनीति में एक अनूठा मॉडल बन गया है।

यह नई योजना कोई अलग पहल नहीं है, बल्कि उस कल्याणकारी रणनीति का विस्तार है, जिसे नीतीश वर्षों से गढ़ते आ रहे है। पंचायतों और शहरी निकायों में महिलाओं को दिये गये 50 प्रतिशत आरक्षण ने जमीनी लोकतन्त्र का कायाकल्प कर दिया है। पुलिस भर्ती और सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण से सरकारी नौकरियों और विभागों का स्वरुप ही बदल गया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान सरकार ने विशेष सैल बनाया व हैल्प लाइन नंबर जारी किये

जयपुर, 10 सितम्बर। नेपाल में हाल ही में हुई हिंसात्मक घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वहां रह रहे प्रवासी राजस्थानियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से सीधे बातचीत कर मौजूदा हालात की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि नेपाल में उत्पन्न हालात हृदय-विदारक हैं और राज्य सरकार वहां मौजूद हर राजस्थानी नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

- मुख्यमंत्री भजन लाल ने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से बात कर निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्थान पुलिस मुख्यालय में एक विशेष सैल का गठन किया गया है, जो नेपाल में फंसे भारतीयों की सहायता के लिए कार्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका भी पूरी रुचि ले रहा है, नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो और, उसका "आदमी" प्र.मंत्री की कुर्सी पर बैठे

अमेरिका ने अपने पिछलग्गू राजनीतिज्ञों में से तीन को चुना है प्र.मंत्री पद के उम्मीदवार के रुप में

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 सितंबर। नेपाल में राजनीतिक नैतिकता की भारी कमी को लेकर लंबे समय से आक्रोश पनप रहा है। बीते 17 वर्षों में नेपाल में 14 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। आम धारणा यह है कि सभी दल सत्ता लोलुप, भ्रष्ट और भाई-भतीजावादी हैं।

हर साल औसतन 8 लाख युवा नेपाल छोड़ते हैं, न केवल उच्च वेतन और मध्यम दर्जे की नौकरियों के लिए बल्कि दिहाड़ी मजदूरी तक के लिए।

बेरोजगारी बहुत अधिक है और भआरी गरीबी है। यही कारण है कि देश में बड़े पैमाने पर असंतोष पनपा है। ओली सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध, जो कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक साल बाद लागू किया गया, जैनरेशन ज़ैड को स्वीकार नहीं था,

यह आखिरी तिनका साबित हुआ-जिसने सब्र का बांध तोड़ दिया।

आज के उन्य देशों की तरह नेपाल में भी युवा अपनी भावना की अभिव्यक्ति, मनोरंजन और संवाद के लिए सोशल मीडिया निर्भर रहते हैं। ओली को नेपाल में एक अधिनायकवादी नेता के रूप में देखा जाता है। सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने उस पर बैन लगाया। जिससे युवा वर्ग भारी नाराज हो गया और उन्होंने इसे अलोकतांत्रिक कदम करार दिया।

इस पूरे घटनाक्रम में शासन परिवर्तन के ऑपरेशन के संकेत मिलते हैं।

एक है रवि लामिछाने जो दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजे गए थे। मंगलवार को भीड़ ने ललितपुर जिले के नक्खु जेल पर हमला कर 1500 कैदियों को छुड़ा लिया-इनमें रवि लामिछाने भी शामिल थे।

- पहला नाम है राबी लामिछाने का, ने कुछ समय के लिये, दिसम्बर 2022 से जनवरी 2023 तक, नेपाल के उपप्रधानमंत्री व गृह मंत्री रह चुके हैं तथा भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार थे, पर युवा आंदोलनकारियों ने नाखु जेल तोड़कर सभी कैदियों को रिहा करवाया था, उनमें राबी लामिछाने भी थे।
- दूसरा नाम काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह का है। शाह घोर भारत विरोधी विचारों के व्यक्ति हैं, और उनके ऑफिस में अखण्ड नेपाल का नक्शा लटका हुआ है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का काफी हिस्सा प्रस्तावित अखण्ड नेपाल में दिखाया गया है।
- तीसरा नाम हरका समपंग का है, जो वर्तमान में धारन के मेयर हैं।
- अमेरिका के समर्थन में नेपाल में दो और ताकतें हैं। नेपाल के इसाई, जिनकी संख्या अनियंत्रित धर्मपरिवर्तन से बहुत बढ़ी है, पिछले कुछ सालों में, और दूसरी ताकत है, एनजीओ जिन्हें अमेरिका से भारी आर्थिक मदद व अनुदान मिलता है। ये दोनों ताकतें भी चाहेंगी कि कोई अमेरिका का समर्थक ही प्र.मंत्री बने।

उन्हें अमेरिका का करीबी माना जाता है।

दूसरे है बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन। ये काठमांडू के मेयर है, जिन्हें भारत विरोधी रवैये के लिए जाना जाता है। उनके कार्यालय में "अखंड नेपाल" का नक्शा लगा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिस्से शामिल हैं।

तीसरे हैं धरान के मेयर हर्का सम्पंग, जो अमेरिकी समर्थक माने जाते हैं। ये तीनों को "अमेरिकी पिट्ठू" हैं, जबकि ओली को चीन समर्थक नेता के रूप में देखा जाता है।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नेपाल में 2015 के भूकंप के बाद से अमेरिका की भूमिका लगातार बढ़ती गई है। ईसाई मिशनरी संगठनों की नेपाल में घुसपैठ हुई है। बिना किसी रोक टोक के बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराए गए हैं। अब बड़ी आबादी ईसाई यहां तक कट्टर इवेन्जिकल बन गईं है जो बाइबल को ही अंतिम सत्य मानते हैं। इन पर अमेरिकन बैपटिस्ट और ईवेंजेलिकल संगठनों का नियंत्रण है।

नेपाल में भारी संख्या में एनजीओ हैं, जिनका मुख्य वित्तपोषण अमेरिका से होता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिनका जनमत निर्माण में बड़ा हाथ है,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नेपाल हिंसा में मृतकों की संख्या 30 पहुंची

काठमांडू, 10 सितंबर। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर हुए उग्र प्रदर्शन में मृतकों की संख्या बुधवार को बढ़ कर 30 हो गयी, जबकि 1,033 लोग घायल हो गये, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

- देश भर के 28 अस्पतालों में 1033 घायलों का इलाज चल रहा है।

कांतिपुर समाचार पत्र ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से देर शाम यह जानकारी दी। इसमें बताया गया है कि आंदोलन में कुल मरने वालों का आंकड़ा बढ़ कर 30 हो गया है। देश भर के 28 अस्पतालों में 1,033 घायलों का उपचार किया जा रहा है, जबकि 713 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है।